we push ahead with naphtha-based fertiliser because technologically that is the most economic. We are not going in for coal-based fertilisers. Even the coal-based fertilisers thought of have been given up and we are concentrating just now on naphtha-based fertilisers.

श्री विश्राम प्रसाद : पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया...

अध्यक्ष महोदय : राजस्थान का ही पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश का नहीं ।

श्री विश्राम प्रसाद : पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री यशपाल सिंह : मैं राजस्थान के बारे में पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत देर से उठे हैं ।

श्री यशपाल सिंह : ओरिजन तो मेरा राजस्थान से ही हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अर्सा हो गया है निकले हुए । ओरिजन बहुत देर से याद आया है ।

Mahalanobis Committee's Report on National Income

\+

*662. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Kinder Lal:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Mahalanobis Committee's report on the distribution of National Income has been accepted by Government;

(b) if not, the reasons for the delay; and

(c) when it is likely to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The Committee on Distribution of Income and Levels of Living headed by Prof. P. C. Mahalanobis has so far submitted only Part I of its report. This has already been placed on the Table of the House. Part II of the Committee's report has yet to be received by the Government. Until this is available, the Government cannot take a total view. Government has already initiated action in the form of the Monopolies Commission whose recommendations are being considered. The conclusions arrived at in Part I of the Mahalanobis Committee Report have, naturally influenced the formulation of policies in this field.

श्री यशपाल सिंह : यह चर्चा सदन में पिछले पांच सालों से चल रही है और महलनबीस कमेटी भी बैठी थी और उसके बाद मोनोपोलीज कमीशन भी नियुक्त किया गया । लेकिन हम देखते हैं कि अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बिल्कुल मिटते जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि महलनबीस कमेटी की रिपोर्ट में या मोनोपोलीज कमीशन की रिपोर्ट में क्या कोई इस तरह का प्राविजन है कि यह प्रक्रिया जो है गरीबों को चूसने की यह बन्द हो जाए ?

श्री ल० ना० मिश्र : माननीय सदस्य ने देखा होगा कि पहला भाग जो है रिपोर्ट का और जिसको यहां पर रखा जा चुका है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा कनक्ल्यूसिव एवीडेंस नहीं मिल सका है जिससे यह पता चले कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनईवन हुआ हो । यह जो उन्होंने कहा है वही म आपको बता रहा हूं । जहां तक मोनोपोलीज कमिशन की रिपोर्ट का ताल्लुक है माननीय सदस्य ने उसको भी देखा होगा और उनको यह भी पता होगा कि उसमें नोट आफ डाइसेंट मि० दत्त का है और उसमें उन्होंने कहा है कि कन्सेन्ट्रेशन आफ वैल्थ हो रहा है । लेकिन जब तक दूसरा भाग न आए महलनबीस कमेटी

की रिपोर्ट का, कोई फैसला लेना मुश्किल है। इसका कारण यह भी है कि पहली रिपोर्ट में उन्हों ने लिखा है कि सरकार को चाहिये कि हमारी रिपोर्ट का जो दूसरा भाग है उसका वह इंतजार करे और दोनों को मिला जुला कर किसी निर्णय पर पहुंचे ।

श्री यशपाल सिंह : महलनबीस कमेटी तो एक गैर-सरकारी कमेटी है, जिस को सरकार एड देती है । आखिर सरकार कब तक उस पर डिपेंड करेगी ? पिछले अठारह सालों में एग्रीकल्चर की पैदावार घटती जा रही है और उस के लिए सरकार कोई भी सुविधा नहीं दे सकी है, ताकि हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सके । क्या सरकार महलनबीस कमेटी पर डिपेंड करने के बजाय अपनी किसी कमेटी के सुपुर्द यह काम करेगी, जो कि अपनी रिपोर्ट वक्त पर दे सके ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह गैर सरकारी कमेटी कहां है । नान-आफिसर लोग भी हैं, लेकिन इसकी स्थापना सरकार ने की थी और इसकी रिपोर्ट भी आई है । जहां तक खेती का सवाल है उसका इस कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है । यह कमेटी तो डिस्ट्रिब्यूशन आफ वैल्थ के बारे में है ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मंत्री महोदय बताया है कि समिति ने अपना प्रथम प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है और उस की ओर से दूसरा प्रतिवेदन अभी तक नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक दूसरे प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, क्या समिति ने कोई मध्यवर्ती प्रतिवेदन दिया है । समिति के प्रथम प्रतिवेदन में राष्ट्रीय आय के वितरण में असमानता का उल्लेख किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतवर्ष के बहुत से अर्थ-शास्त्रियों ने सरकार को एक स्मृतिपत्र प्रस्तुत किया है कि महलनबीस कमेटी ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में राष्ट्रीय आय के वितरण में असमानता को दूर करने के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उस पर पुनर्विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सवाल इतना लम्बा है कि मैं पहला हिस्सा भूल गया हूं ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं भी भूल गया हूं, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं । समिति की प्रथम रिपोर्ट को करीब दो साल पहले—फ़रवरी या मार्च, 1964 के करीब सदन के सामने रखा गया था । माननीय सदस्य ने उस रिपोर्ट को पढ़ा होगा । उन्होंने लिखा था कि देश में आर्थिक विषमता के बारे में दो तरह की रायें हैं । उन्होंने कहा कि कोई कान्क्लूसिव एविडेंस नहीं मिल सका कि देश में राष्ट्रीय आय का अनईवन डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि कान्सेन्ट्रेशन आफ वैल्थ हुआ है । उन्होंने इस बात को माना है और मानोपलीज कमीशन के श्री दत्त ने भी यही राय दी है । मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि अर्थ-शास्त्र के विद्वानों ने कोई मेमोरेंडम दिया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित इस कमेटी की रिपोर्ट का दूसरा भाग आज तक सदन में इसलिए नहीं आ सका है, क्योंकि इस देश के पैसे वालों और उन पैसे वालों के समर्थक सरकार के व्यक्तियों का इस बारे में दबाव है, अगर यह झूठ है, तो आज तक यह रिपोर्ट क्यों नहीं आई है ।

श्री ल० ना० मिश्र : दबाव तो कुछ है नहीं और कमेटी को पूर्ण स्वतंत्रता है ।

श्री भागवत झा आजाद : उन को निकाल बाहर कीजिए ।

श्री ल० ना० मिश्र : इस कमेटी के सदस्य बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं । यह कहना उन के साथ ज्यादती होगी—यह अनफेयर होगा—

कि इतने बड़े-बड़े लोग किसी दबाव के नीचे काम कर रहे हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad: Why are they not submitting if they are so big?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक रिपोर्ट में देरी होने का सम्बन्ध है, हम इस बारे में उनसे बात करते रहे हैं और हमने आग्रह किया है कि रिपोर्ट जल्दी दी जाये, लेकिन वे नहीं दे सके, क्योंकि समिति के कुछ सदस्य ऐसे लोग हैं, जो देश में अपने काम में लगे हुए रहते हैं और हमेशा विदेश भी जाया करते हैं। नतीजा यह होता है कि सैकेंड रिपोर्ट मिलने में देरी हुई है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि धनी या अमीर लोगों के दबाव के कारण यह रिपोर्ट नहीं आती है। सरकार इस बात के लिए बहुत आतुर है कि रिपोर्ट जल्दी आए और हम उस पर अमल करना चाहते हैं।

Shri S. M. Banerjee: I would like to know if it is a fact that today even after 19 years of independence this country has become a country of poverty and plenty, both. After the submission of the first part of the report by Prof. P. C. Mahalnobis, another commission was appointed, known as the Monopolies Commission, just to sidetract the first one. I would like to know whether the Government is likely to implement any recommendation of any commission concerning the concentration of wealth. Apart from that, what are the steps taken by the Government to remove this disparity in incomes?

Shri L. N. Mishra: The hon. Members must have studied the first report of the Mahalnobis Committee. There were three terms of reference. The first report referred to the second and third, what you call disparity in distribution of income and other concentration of wealth. The first part deals with these two subjects. The second part is about review of standard of life during the Second Plan. We are awaiting the report on that subject.

About the implementation part, the Monopolies Commission's recommendations are under consideration, and I believe more concrete action in that connection would be taken very soon, not before long at least.

Mr. Speaker: We should not take so much time on one question. The answer has come.

Shri S. M. Banerjee: I am not takink so much time but I seek your guidance. My question was this. The commission was appointed but the recommendation has not been implemented. Then the other commission was appointed to sidetrack the first one which was announced by T. T. K.

Mr. Speaker: These are comments.

Shri S. M. Banerjee: Is that recommendation to be implemented at all? I am afraid that they may not be implemented at all.

Shrimati Ramdulari Sinha: Are the Government aware that concentration of economic power in the hands of a few might lead to misdirection in investment and if so is there any proposal before the Government to take steps to curb concentration of such economic power for equitable distribution of national income to the common man?

Shri L. N. Mishra: About the evils there is no dispute. Concentration of economic power in a few hands has got many evils. About the steps to prevent this, it is the objective of our plan. We are opposed to concentration of wealth in a few hands. We are moving in that direction.

श्री सिंहासन सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि महलनबीस कमेटी की रिपोर्ट आए या न आए—कमेटी और न कमेटी, रिपोर्ट और नो रिपोर्ट—, क्या गवर्नमेंट खुद यह नहीं जानती है कि देश में धनी और धनी हो गया है और सब धन कुछ घरों में ही निहित हो गया है ; अगर वह इस बात को जानती है, तो क्या उस ने स्वत: इस बात पर विचार किया है और स्वत: कोई स्कीम निकाली है कि धन को केवल कुछ स्थानों में एकत्रित

न होने दे कर उस का ठीक वितरण किया जाये ।

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा कि माननीय सदस्य, श्री भागवत झा आज़ाद ने कहा है, आदरणीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग़ में यह बात आई थी और उन्होंने इस समिति की स्थापना की थी । उस का कारण यह था कि सरकार के सामने यह बात आई थी और देश में यह हवा थी । यह सत्य भी है कि धनी और धनी हुए हैं । मैं यह नहीं मानता हूं कि ग़रीब और ग़रीब हो गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि धनी और धनी हो गए हैं । समिति की रिपोर्ट आई है । मैंने अपने आन्सवर में कहा है :

> "The conclusions arrived at in Part I of the Mahalanobis Committee Report have, naturally influenced the formulation of policies in this field."

इसलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आब-जेक्टिव्ज़ और उद्देश्यों में इस बात का ख़याल रखा गया है ।

Shri Warior: May I know whether it is not a fact that the party in power has already in a party way taken a decision on the monopolies commission and that is why the recommendations including the dissenting note are not implemented?

Shri L. N. Mishra: There is no question of anything not being implemented; it is being considered; it is in fact before the Cabinet and in a few days time the decision will be announced.

Shri Joachim Alva: Is the Government aware that the hundred wealthy families of India are today wealthier than at any time in the history of India, Puranic, Muslim, British, Congress and now, and also that these firms control two-thirds of the total advance of the banks of India? Is the Government aware of the existence of the monopolies commission in U.K., on the pattern of which we have built out organisation and that there in U.K. the monopolies commission is sitting regularly and firing even the biggest companies; in a recent case they fined the tyre company a big sum? Why not Government take some measures and do something quick?

Shri L. N. Mishra: The evil is there. The commission was appointed and the report has come. The hon. Member knows the recommendations; some of the recommendations are very radical and drastic and Government will consider it and will try to implement it as far as possible.

Shifting of Government Offices

***663. Shri N. R. Laskar:** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3379 on the 7th April, 1966 and state:

(a) the up-to-date progress made in shifting Government Offices in view of congestion in Delhi area;

(b) whether some Ministries/Attached Offices are reluctant to move away from the central location; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Urban Development (Shri Bhagwati): (a) Three offices out of the sixteen proposed to be shifted outside Delhi have so far moved out. They are:—

(i) The Central Water and Power Commission (Water Wing) to Faridabad.

(ii) The National Sample Survey Directorate (Bulk portion) to Faridabad.

(iii) The Fertilizer Corporation of India (part only) to Gorakhpur.

(b) Yes.